का धान बोने का लक्ष्य निश्चित किया गया है तथा इस सम्बन्ध में खाद तथा कीटनाशी दवाइयों के बारे में लक्ष्य तथा सम्भरण योजनाओं का ब्योरा क्या है ;

(ख) उपरोक्त क्षेत्र में सिंचाई की समुचित व्यवस्था करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ग) धान की उपरोक्त किस्म के अलावा और कौन-कौन सी किस्में बोई जायेंगी, इस कार्य के लिये, कितनी जमीन में बुआई होगी और इस सम्बन्ध में किन-किन उपायों को काम में लाया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे): (क) से (ग). खरीफ 1967 के दौरान कुल लगभग 41.36 लाख एकड़ भूमि में धान की अधिक उपज वाली किस्मों को बोने का लक्ष्य है । जितने क्षेत्र में विभिन्न किस्मों को बोना है वह निम्नलिखित हैं :—

1. ताइचुंग तेटिव-1	19.03 लाख एकड़
2. एडीटी-27	8.65 लाख एकड़
3. ताइनान-3	3.12 लाख एकड़
4. ताइचुंग-65	3.32 लाख एकड़
5. आईआर-8	2.20 लाख एकड़
6. अन्य किस्में	5.04 लाख एकड़
	41.36 लाख एकड़

उपरोक्त कार्यक्रम उन क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा जिनमें सिंचाई/वर्षा होगी ।

राज्य सरकारों ने लक्षित क्षेत्र में बोने हेतु इन किस्मों के बीज सप्लाई करने के लिये अपने प्रबन्ध किए हैं । यदि कमी पड़ी तो जरूरतमन्द राज्यों को उनकी प्रार्थना पर राष्ट्रीय बीज निगम आवश्यक मात्रा देने का प्रबन्ध करेगा ।

जहां तक उर्वरकों का संबंध है उपरोक्त क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिये राज्यों को 1.5 लाख टोन्ज नाइट्रोजन उपलब्ध किया जाएगा । इस मात्रा का लगभग 55 प्रतिशत भाग पहले ही त्रिमासिक अप्रैल, जून 1967 के लिये केन्द्रीय पूल से राज्यों को अलाट कर दिया गया है । जहां तक कीट-नाशक औषधियों का सम्बन्ध है कार्यक्रम की जरूरतों को पूरा करने के लिये राज्य सरकारों के पास पर्याप्त स्टाक है ।

अधिक उपज वाली किस्म कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि ऋण की जरूरतों को पूरा करने के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया कोआपरेटिव के सदस्यों को पर्याप्त ऋण स्वीकृत करने को सहमत हो गया है ।

गैर-सदस्यों के मामले में राज्य सरकारें गत वर्ष की तरह किसानों को तकावी ऋण देने का प्रबन्ध करेंगी ताकि अधिक उपज वाली किस्मों की खेती शुरू की जा सके । 1967-68 के बड़े कार्यक्रम को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले उदार ऋणों का पूरा लाभ उठायें । राज्य सरकारों से जो विचार-विमर्श हुआ उससे संकेत मिलता है कि 1967-68 के दौरान अधिक उपज वाली किस्म कार्यक्रम के लिये अल्प-कालीन ऋण की जरूरतों को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

दिल्ली शाहदरा में कूड़ा खाद का प्रयोग

952. श्री महाराज सिंह भारती : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहदरा (दिल्ली) में दग्ध किये जाने वाले कूड़े को

इस समय कूड़ा खाद बनाने के लिये प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि नीची भूमि को भरने के लिये प्रयोग किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कूड़े में से जिससे खाद बनाई जाती है कंकड़, पत्थर, शीशे के टुकड़े आदि नहीं निकाले जाते हैं और क्या यही कारण है कि किसान दिल्ली की खाद नहीं खरीदते हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी सहयोग से एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने तथा इस कूड़ा खाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) तथा (ख). यह सच है कि दिल्ली नगर निगम इस समय कूड़े को नीची भूमि को भरने के लिये प्रयोग में ला रहा है। कूड़े को इकट्ठा करने की विधि द्वारा और विशेषकर नगर निगम द्वारा शाहदरा कूड़े के भण्डार में इकट्ठा किये गए कूड़े में कंकर पत्थर, शीशे के टुकड़े आदि अवश्य पाए जाते है। इस कारण किसान इस खाद को नहीं खरीदते। अतः उन्हें यह खाद मुफ्त उठाने की अनुमति दी जाती है। दिल्ली प्रशासन किसानों में बेचने के लिये इस खाद को छानने का प्रबन्ध कर रहा है।

(ग) जी नहीं।

राज्यों में खाद्यान्नों के मूल्य

953. डा० साहबेब प्रसाद : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राज्यों में, जहां गैर कांग्रेसी सरकारें है, वस्तुओं के मूल्य, विशेषकर खाद्यान्न के मूल्य गिर गये है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) कांग्रेसी सरकारों और गैर-कांग्रेसी सरकारों वाले राज्यों में खाद्यान्न सहित कृषि वस्तुओं के भावों में बढ़ोतरी और गिरावट के मामले में, जिनके बारे में खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में सूचना उपलब्ध है ; कोई भेद-भाव नहीं देखा गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Sale of gift clothes in Bihar

954. **Shri K. N. Pandey:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that gifts of clothes from Europe and North America distributed among the destitute persons in Bihar are sold in the open market to shopkeepers; and

(b) if so, the steps being taken to check this practice?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). Gifts of foreign cloths have been received from Europe only by the Central Relief Committee (India), New Delhi for distribution among the destitutes in the scarcity affected areas. The Bihar Relief Committee, who were entrusted by the Central Relief Committee with the distribution of these clothes in the scarcity-affected areas of Bihar have no direct knowledge of the sale of such clothes in the open market to the shopkeepers.

Detention of Vessels at Port Blair

955. **K. R. Ganesh:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the mainland-island Vessel 'M.V. Nicobar' on her voyage ex-Port Blair on the